Issue XIX-XX
March-April
2016

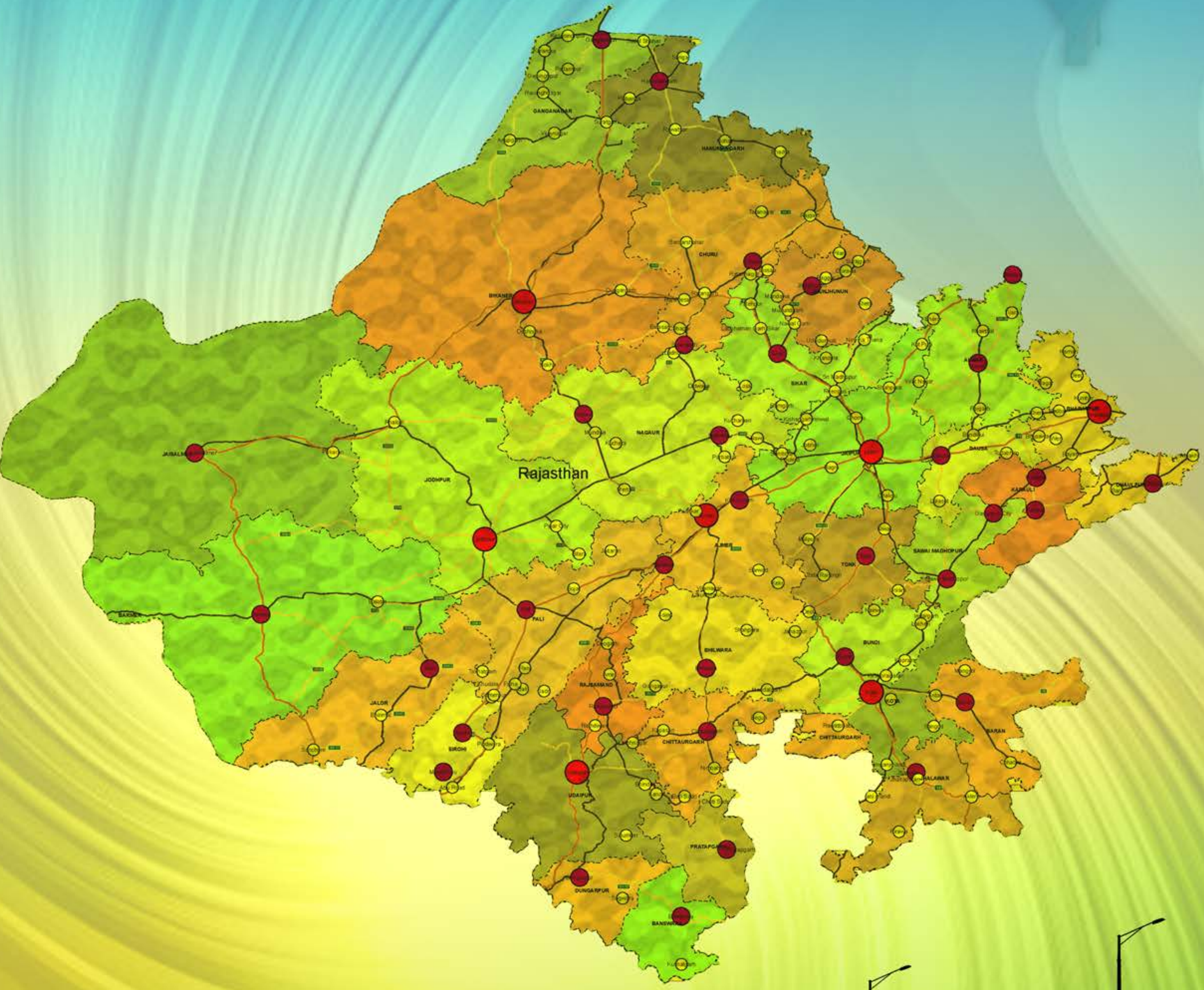

CMAR

City Managers Association Rajasthan

Promoting Excellence in City Management...

Editor in Chief:	**Shri Purushottam Biyani (IAS)** (Director cum Special Secretary, LSGD, GoR)
Editorial & Compilation:	**Dr. Himani Tiwari** (Coordinator, CMAR) **Mr. Sharawan Kumar Sejoo** (Research Assistant, CMAR)
Digital Typesetting:	**Mr. Arjun Pal** (IT Expert, CMAR)
CMAR Team:	**Mr. Sandeep Nama** (Research Investigator, CMAR) **Mr. Sitaram Verma** (Assistant, CMAR)

Our sincere thanks to:

Smt. Sanchita Bishnoi (RAS)	(Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Smt. Preeti Mathur (RAS)	(Project Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)	(Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Smt. Madhu Rathore (R.Ac.S.)	(Sr. Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri R.K. Vijayvargia	(Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Pintu Lal Jaat	(Executive Officer, Municipal Board Kuchera)
Shri Vinaypal	(Executive Officer, Municipal Board Baggar)
Shri Amar Deep Singh	(Project Coordinator, CUTS International)
Shri Brijesh Pareek	(PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)

For suggestions/feedback please write to:

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies

G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,

Telefax: 0141-2229966, website: www.cmar-india.org, Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

Contents

मुख्यमंत्री ने कार्टिस्ट ऑटो मोबाइल आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया	1
जयपुर शहर में कचरे के निस्तारण के लिए हुआ एमओयू	4
बग्गड़ नगरपालिका की अनूठी पहलः वाट्सएप ग्रुप पर होगा समस्या का समाधान	5
मेयर कांफ्रेस में शहरी विकास व जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर किया मंथन	7
जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड (Board of Director) की प्रथम बैठक सम्पन्न	8
अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों को सीवरेज, वाटर सप्लाई के लिए 620 करोड़ रूपये स्वीकृत	9
नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम के लिए बोर्ड का गठन	10
Door to Door Collection in Kuchera	11
राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) की बैठक आयोजित	14
शहरी क्षेत्र की योजनाओं (NULM, LED, SBM, AMRUT and E-Governance etc.) की समीक्षा	15
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का नाम परिवर्तन	15
Press Coverage	16

मुख्यमंत्री ने किया कार्टिस्ट ऑटो मोबाइल आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन

वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल, 2016 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने नारायण सिंह सर्किल स्थित होटल नारायण निवास में नगर निगम जयपुर के तत्वावधान में आयोजित कार्टिस्ट ऑटो मोबाइल आर्ट फेस्टीवल–2016 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रदर्शनी में नामचीन कलाकारों द्वारा चौपहिया वाहनों एवं कैनवास पर पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन एवं ऑटो मोबाइल आर्ट को दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अवसर पर जयपुर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुने जाने पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लोगो (Logo) का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि किसी भी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिये उचित मंच उपलब्ध करवाना ही उन्हें समुचित प्रोत्साहन देना होता है। हमने इसी सोच के साथ जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स और बस शेल्टर्स के जरिए जोगी आर्ट को प्रदर्शित किया जिसकी पर्यटकों एवं जयपुर के वासियों ने सराहना की। अनेक लोग उत्साह के साथ इन पेंटिंग्स के साथ सैल्फी लेते भी दिखाई दिए जो इस बात का प्रतीक है कि लोग इस प्रयास को और जोगी कला को पसन्द कर रहे हैं। कार्टिस्ट प्रदर्शनी की छोटी सी शुरूआत अल्बर्ट हॉल से की गई थी जो आज बड़े रूप में हमारे सामने हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि लन्दन की सड़कों पर दौड़ रही कैब में वहां की कला व रंग दिखाई देते हैं तो हमारे यहां ऑटो रिक्शा में भी राजस्थान की कला क्यों नहीं दिखाई दे सकती। इस दिशा में कार्टिस्ट प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राज्य सरकार ऐसी कलाओं और कलाकारों को सदैव प्रोत्साहन देती रहेगी।

उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन में आने–जाने वाले यात्रियों को स्थानीय महत्व की कलाओं आदि की जानकारी देने के लिए हमने सवाई माधोपुर, जयपुर के रेलवे स्टेशनों, जोधपुर में फड़ आर्ट, उदयपुर में शहर के नयनाभिराम चित्रें, बीकानेर में बादल महल, अजमेर में कैलीग्राफी कलाओं का प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पर किया है जिसे लोगों की सराहना मिल रही है। राज्य में थीम आधारित नृत्य, संगीत, साहित्य और नाटक को जयपुर, उदयपुर, पुष्कर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में आयोजित समारोहों को भी प्रोत्साहित किया हैं। जिसके सुखद परिणाम रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का पूरे मनोयोग से अवलोकन किया। प्रत्येक मण्डप में कलाकारों से उनकी कला के बारे में जानकारी हासिल की, उनके साथ फोटो खिंचवाए और सभी कलाकारों को इस कला को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर जयपुर नगर निगम के महापौर निर्मल नाहटा ने मुख्यमंत्री को प्रदर्शनी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हैरिटेज दिवस की पूर्व संध्या पर युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने एवं प्रदेश की कलाओं की विशिष्टता को जन–जन तक पहुंचाने के लिये राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप महाराजा स्कूल ऑफ आर्टस द्वारा तीन स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कार्टिस्ट प्रदर्शनी में प्रमुख कलाकारों के साथ बड़ी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र–छात्राएं अपना हुनर दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व में आयोजित प्रदर्शनी में विजेता रहे स्कूलों और कॉलेजों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। नारायण निवास पर लगाई गई प्रदर्शनी में मुम्बई के जेजे स्कूल ऑफ आर्टस, शांति निकेतन, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट, देहली स्कूल ऑफ आर्ट के 100 मेधावी

विद्यार्थियों ने ऑटो मोबाइल थीम पर कार्य करेंगे। इसके तहत वाहनों पर पेंटिंग की जायेगी।

कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत, उप महापौर श्री मनोज भारद्वाज, नगर निगम के आयुक्त श्री आशुतोष पेण्डणेकर, समाजसेवी श्री सुरेश पाटोदिया सहित विभिन्न कलाओं से जुड़े कलाकार एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

जयपुर शहर में कचरे के निस्तारण के लिए हुआ एमओयू

जयपुर शहर से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 12 सौ मेट्रिक टन कचरे का अब समय पर निस्तारण हो सकेगा। कचरे से (कंपोस्ट) खाद बनाकर उसे बाजार में बेचा जाएगा। इसके लिए नगर निगम और दो कम्पनियों के बीच 6 अप्रैल, 2016 को एमओयू हुआ। इस एमओयू के तहत नगर निगम जयपुर कंपोस्ट बनाने वाली कम्पनी आईईआईएसएल को शहर से निकलने वाला कचरा उपलब्ध करवायेगा तथा कचरे से बनने वाला खाद्य को बेचा जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने 100 प्रतिशत कचरे के निस्तारण करने के लिए योजना बनाई है।

इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के डिप्टी सेक्रेटरी सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में कचरे का निस्तारण केवल 18 प्रतिशत ही किया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार का पूरे देश के कचरे का अक्टूबर, 2019 तक 100 प्रतिशत निस्तारण करने का मिशन है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी ने जयपुर शहर के विभन्न स्थानों का निरिक्षण किया तथा सफाई के साथ बनाये जा रहे टॉयलेट का भी निरीक्षण किया उन्होने जौहर बाजार, मच्छी मार्केट, झालाना बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, जेएलएन रोड़ तथा सेवापुरा कंपोस्ट प्लान्ट का भी निरीक्षण किया।

उन्होने झालाना बस्ती में बनाये जा रहे टॉयलेट के कार्य को सराहा तथा शौचालय विहिन घरों में जल्द ही शौचालय निर्माण हेतु निर्देशित किया

बग्गड़ नगरपालिका की अनूठी पहल
वाट्सएप ग्रुप पर होगा समस्या का समाधान

''घर–घर कचरा संग्रहण'' योजना, सफाई एवं रोशनी व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग करने व इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किये जाने हेतु नगरपालिका द्वारा वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जिसमें अध्यक्ष/पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, नेताप्रतिपक्ष, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, प्रत्रकारगण एवं नगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी आदि सदस्य है।

इस ग्रुप में कस्बे के किसी भी वार्ड में सफाई व रोशनी से सम्बन्धित कोई भी समस्या/शिकायत ग्रुप में डाली जाती है तो पालिका प्रशासन द्वारा उसकी मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर तत्काल समस्या का समाधान कर ग्रुप में समस्या समाधान होने की पुष्टि की जाती है। इस सम्बन्ध नगरपालिका अध्यक्ष सुशीला बुंदेला ने बताया कि हमारा उद्देश्य आम जनता की शिकायतों/समस्या को निवारण कर जनता को राहत देना है। अधिशाषी अधिकारी विनयपाल महला ने इस सुविधा से ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होने की जनता से अपील के साथ ही कस्बेवासियों से सहयोग मांगा है।

अन्य नगरीय निकाय भी करें ऐसा प्रयास

बग्गड़ नगरपालिका ने वाट्सएप ग्रुप बनाकर पालिका से जुड़ी जन समस्याओं के तत्काल समाधान का जो अनूठा प्रयास किया है यह सराहनिय है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि पालिका प्रशासन व जनप्रतिनिधि जनता के प्रति दायित्वों को लेकर कितने गम्भीर हैं। इस तरह के अनूठे प्रयासों से जहॉ लोगों को बार–बार नगरपालिका में चक्कर नहीं लगाने पड़ेगें, जन समुदाय को अत्यन्त लाभ होगा, साथ ही लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा।

<u>घर–घर कचरा संग्रहण योजना का भी शुभारम्भः–</u>

सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने एवं घर–घर से कचरा एकत्रित कर डम्पिंग पॉइन्ट तक पहुँचाने हेतु नगर पालिका बग्गड़ द्वारा **विश्व महिला सशक्तिकरण दिवस** (08 मार्च, 2016) को शहर की महिलाओं को समर्पित ''घर–घर कचरा संग्रहण'' योजना का शुभारम्भ किया गया। नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक घर तक ''घर–घर कचरा संग्रहण'' हेतु ऑटो टीपर की पहुँच/समय को सुनिश्चित किया गया। वार्ड की महिलाएँ/पुरूष ऑटो टीपर में घर का कचरा डालते है। जिससे वार्ड की रोड़/सार्वजनिक स्थान पर कचरा दिखना बन्द हो गया है। इस योजना का फीडबैक लिया गया जिसमें वार्ड वासियों द्वारा पालिका के इस प्रयास को बेहतर बताया एवं सफाई व स्वच्छता में पूर्व की तुलना में अधिक सुधार देखा गया है।

मेयर कांफ्रेस में शहरी विकास व जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर किया मंथन

नगरीय निकायों के चुने हुए मेयर एवं सभापतियों की 28 अप्रैल, 2016 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा (Mayors Learning Platform) के तहत होटल आमंत्रा, उदयपुर में कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में जीरो वेस्ट मैनेजमेंन्ट व शहरी विकास विषयों पर मंथन किया गया तथा उपस्थित महापौर/सभापतियों ने अपने क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो का जिक्र भी किया। इस अवसर पर कोयूम्बटूर के जीरो वेस्ट मैनेजमेन्ट को समझा और उसके तहत कार्य करने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में नेशनल रिमोट सेंसिग के विषय विशेषज्ञ डॉ. ए.पेरूमल ने भी जी. आई.एस. बेस मेपिंग व शहरी विकास के लिए डाटा बेस मैनेजमेंट की जानकारी दी। जयपुर नगर निगम के मेयर निर्मल नाहटा ने निगम की ओर से जयपुर में स्वच्छता पर किये जा रहे प्रयास की जानकारी दी। उदयपुर नगर निगम के मेयर चन्द्र सिंह कोठारी ने उदयपुर में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण व स्मार्ट सिटी पर किये जा रहे कार्यो की जानकारी साक्षा की।

कार्यशाला में डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति के.के. गुप्ता, बांसवाड़ा नगरपरिषद के सभापति मंजुबाला पुरोहित, कोटा नगर निगम की उपमहापौर सुनिता व्यास, सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान की समन्वयक डॉ. हिमानी तिवाड़ी व कट्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमरदीप सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए।

स्वच्छता पर डूंगरपुर नगरपरिषद में किये जा रहे कार्यो को सराहा

कार्यशाला में डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा डूंगरपुर शहर को स्वच्छ डूंगरपुर बनाने के लिए डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण, खुले में शौच मुक्त, प्लास्टिक पर प्रतिबंध व प्राप्त शिकायतों का सोशल मिडिया से समाधान आदि कार्यो को खूब सराहा गया।

जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड (Board of Director) की प्रथम बैठक सम्पन्न

जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड (Board of Director) की प्रथम बैठक 06 अप्रैल, 2016 को स्वायत्त शासन भवन के कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर निगम जयपुर के आयुक्त श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया एवं जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने के लिए गठित स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की एवं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग, प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी कार्य 15 जून, 2016 से पूर्व प्रारम्भ हो जायेगा। उन्होनें बताया कि जयपुर देश में दूसरा शहर है, जहॉ स्मार्ट सिटी बनाये जाने के लिए गठित कम्पनी की बैठक हुई है।

बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर निगम जयपुर के आयुक्त श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि स्मार्ट सिटी के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यो की शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म कार्य योजना तैयार की गई है तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी में विभिन्न पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही भी की जा रही है।

बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं महापौर नगर निगम जयपुर निर्मल नाहटा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए टाईम लाईन निर्धारित कर कार्य किया जायेगा। इसके लिए कम्पनी द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे है।

बैठक में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) के गठन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्तीय अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर प्रबंध निदेशक रूडसिको, बी.एल. जाटावत, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा, वित्तीय सलाहकार नगर निगम जयपुर श्री गोपाल विजय, मुख्य अभियन्ता श्री सुभाष गुप्ता आदि उपस्थित थे।

अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों को सीवरेज, वाटर सप्लाई के लिए 620.70 करोड़ रूपये स्वीकृत

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की राज्य स्तरीय बैठक 25 अप्रेल को निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई। जिसमें 620.70 करोड़ रूपये वाटर सप्लाई एवं सीवरेज के लिए स्वीकृती किये गये।

जिनमें से 6 सीवरेज परियोजना के लिए राशि 322.90 करोड़ रूपये (भिवाड़ी को 17.79 करोड़, अलवर 90.62 करोड़ रूपये, नागौर 50.13 करोड़ रूपये, बून्दी 46.36 करोड़ रूपये, कोटा 40.00 करोड़ रूपये एवं बारां 78.00 करोड़ रूपये) वाटर सप्लाई की 3 परियोजना के लिए 297.80 करोड़ रूपये (ब्यावर 109.91 करोड़ रूपये, चित्तौढ़गढ़ 87.89 करोड़ रूपये, बून्दी 100.00 करोड़ रूपये) स्वीकृत किये गये है।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व शहर में पेयजल योजना के सशक्तीकरण एवं सेवास्तर को सुधारते हुए (कवरेज आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाएगा तथा अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) प्राथमिकता दी जायेगी। डॉ. मनजीत सिंह ने निर्देश दिये की पूर्व में स्वीकृत वाटर सप्लाई परियोजना की निविदा 7 मई तक जारी की जाये तथा अमृत शहरों को अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय की वेबसाईट को निरन्तर अपडेट की जाये व ई–न्यूट लेटर का प्रकाशन हर तीन माह में किया जावें।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, श्रीमती संचिता बिश्नोई संयुक्त सचिव वित्त विभाग, श्री जाकिर हुसैन, केन्द्रीय नगरीय विकास मंत्रालय तकनीकी अधिकारी श्रीमती रितु पचौरी, मुख्य अभियन्ता स्थानीय निकाय विभाग, श्री के.के. शर्मा, मुख्य अभियन्ता रूडसिको श्री एस.के. गोयल, मुख्य अभियन्ता पी.एच.ई.डी. श्री सी.एम. चौहान, मुख्य नगर नियोजक, इन्द्रा जी वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, आर.के. विजयवर्गीय एवं अमृत योजना में चयनित 29 शहरों के अधिकारी उपस्थित थे।

नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम के लिए बोर्ड का गठन

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड (आरएवीआईएल) और राजस्थान नगरीय अधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) का राजस्थान नगरीय आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (आरयूआईएफडीसीयू) में विलय कर पुनर्गठित निगम राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं अधारभूत निगम (आरयूडीएसआईसीओ) में परिवर्तित किया है। अधिसूचना के अनुसार पर्नगठित राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम की ओर से राज्य में शहरी पेयजल सीवरेज तथा अन्य आधारभूत विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। नवगठित आरयूडीएसआईसीओ निगम के बोर्ड में अध्यक्ष एवं निदेशक नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री होंगे। नगरीय विकास आवासन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव इस निगम के निदेशक होंगे पुर्नगठित निगम के बोर्ड में प्रशासनिक सचिव स्वायत्त शासन स्वायत्त शासन विभाग उपाध्यक्ष एवं निदेशक होंगे तथा सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव वित्त बजट निदेशक एवं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्धक निदेशक होंगे। आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल एवं निदेशक एवं विशिष्ठ शसन सचिव स्वायत्त शासन इसके निदेशक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नवगठित आरयूडीएसआईसीओ बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होंगे।

DOOR TO DOOR COLLECTION IN KUCHERA

Overview

Kuchera is known as "City of Mirdha's". Kucehra is situated on 26^0 59' N & 73^0 58' E. It is about 260 Kms. from the capital of the Rajasthan & 114 kms. from Zonal Headquarter. This city is at the height about 301 Mtr. from mean sea level. This city is having average rainfall of about 357.40 MM. There is no railway facility in kucehra city & nearest railway station is at Marwar, Mundwa which is 20 Kms. distance from Kuchera.

As per the master plan of Kucehra, it was established as 'Municipal Board Kucehra' in 1976. Municipal Board Kuchera is having about 12 sq. kms. area as peripheri. Municipal Board Kucehra comprises of 20 wards in present. As per census 2011, urban population of Kucehra is about 23326. This area is situated on right side of NH 89, Ajmer to Nagaur. There are various temples of different socities such as Karan Balaji temple, Bheru Ji temple, Ganesh temple etc. Kuchera is beautified with fabulous gardens. Kuchera have 3 National saving banks such as SBBJ, PNB, RMGB. Kuchera is also having a governemnt hospital facility.

OVERVIEW OF WASTE GENERATION

- The growing concern for environmental issues and the goal of sustainable development have become major concerns for the management of solid waste. As a result, it is now in forefront of the public agenda.
- Legislation and regulations have been introduced at local and national levels to direct & develop waste management & techniques for appropriate waste treatment & disposal
- As per the Municipal solid waste (Management & Handling) rule 2000 notified by MoUD, it is mandatory for all ULB's to ban littering of solid waste, door to

door collection & its transportation in closed vehicle system. Recovery of recyclable material, processing of day to day waste generation and minimum transfer of process remnants to scientifically developed land fill sites are mandatory.

- Bio medical waste should not enter in MSW collection.
- Door to door services is considered for 55% of total household.
- Waste generation in remaining 45% households will be collected from community bins.
- During waste collection, the collected waste form to bins is segregated in to Dry waste (Plastic, Paper & Non Bio Degradable) wet waste (Manly bio degradable).

MODES OF TRANSPORTATION

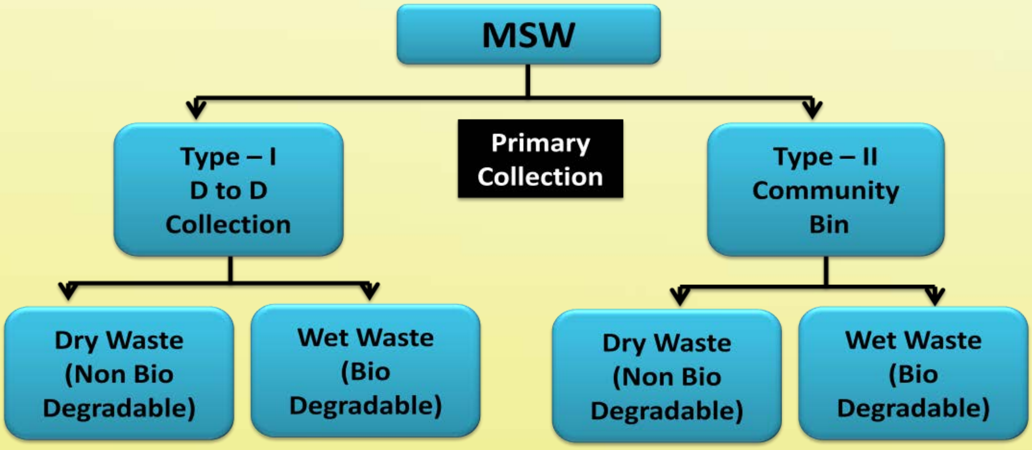

Door to Door collection in Municipal Board Kuchera

As per guideline, orders & circulars DLB, Municipal Board Kuchera which have 20 wards is divided in to 5 Zone for the purpose of Door to Door waste collection. Each zone has Auto Tripper separately. List of 5 zones along with no. of wards 5 Zone is given below:-

Zone No.	No of wards	No. of Auto Tripper
1	1, 2, 3, 4	1
2	5, 6, 7, 8	1
3	9, 10, 11, 12	1

4	13, 14, 15, 16	1
5	17, 18, 19, 20	1

Municipal Board Kuchera appointed a contractor by the process of NIT for Door to Door Collection as per direction of DLB Jaipur. Contractor appointed one auto tripper zone wise separately & also appointed driver with employs for collection & transportation waste to processing site (Disposal Site).

<u>COMPARATIVE OF DOOR TO DOOR COLLECTION AFTER & BEFORE</u>

BEFORE	AFTER
There were various small waste generated places in kuchera otside the houses.	Auto tripper collects the waste from Door to Door by ringing the bell due to which small waste generated places are removed.
Frequency of diseases caused due to poor sanitary conditions like diarrhoefever, skin rashes etc.	Probability of diseases has decreased eventually due to cleanliness and better sanitation
Blockage of drains due to careless littering	Due to D2D collection, the littering is stopped and as a result, there occur no blockage of drains
Pollution of the roads, house etc due to spread of waste	Small open dumping places are cleaned and utilised for parks etc.
Open land and dumping places all around creating nuesense	The waste collected is now transported to disposal site where it is further treated for various uses as fertilizers, material for construction site etc.

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) की बैठक आयोजित

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) की कार्यकारिणी समिति की बैठक 29 मार्च, 2016 को दोपहर 12:30 बजे मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित की गई।

बैठक में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि संचालन के लिए वर्ष 2010–11 में बनाये गये दिशा–निर्देशों में संशोधन के लिए स्वायत्त शासन विभाग को निर्देशित किया गया। वर्तमान में जारी–निर्देशों में आंशिक संशोधन कर शहरी परिवहन की आधारभूत सुविधा जैसे फुटपाथ रखरखाव, ट्रेफिक सिग्नल तथा साईकिल ट्रेक बनाने का कार्य भी शामिल किये जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में जयपुर, कोटा व अजमेर में संचालित बस कम्पनियों की संचालन हानि के विरूद्ध राशि स्वीकृत की गई, जिसमें जयपुर के लिए 24 करोड़, अजमेर के लिए 4.50 करोड़ एवं जोधपुर के लिए 1.40 करोड़ राशि स्वीकृत की गई। जोधपुर में पार्किंग परियोजना के लिए ब्याज रहित राशि रूपये 11.57 करोड़ स्वीकृत किये गये। माउण्ट आबू में पार्किंग परियोजना के तहत 13 करोड़ रूपये तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को बगराना में डिपो के निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपये आवंटन की स्वीकृती प्रदान की गई। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा व ई–चालान के लिए 9.50 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग श्री अशोक जैन, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह, अध्यक्ष जयपुर मेट्रो श्री अश्विनी भगत, सचिव परिवहन विभाग श्री पी.के. गोयल, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान रोड़वेज श्री राजेश यादव, निदेशक व विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन श्री पुरूषोत्तम बियाणी तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

शहरी क्षेत्र की योजनाओं (NULM, LED, SBM, AMRUT and E-Governance etc.) की समीक्षा

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के कांफ्रेस हॉल में 21 अप्रैल को जयपुर, कोटा एंव भरतपुर तथा 22 अप्रैल को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर संभागों की नगरीय निकायों में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

समीक्षात्मक बैठक के प्रथम दिन (जयपुर, कोटा एवं भरतपुर) एवं द्वितीय दिन (जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर) की निकायों के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग श्रीमती संचिता बिश्नोई ने समीक्षा की ओर सभी अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होनें उपस्थित अधिकारियो को निर्देशित किया की वह अपनी निकायों में संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करे तथा अपने स्तर पर भी प्रत्येक माह में दो बार समीक्षा की जायें

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का नाम परिवर्तन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का नाम में परिवर्तन कर ''दीनदयाल अन्तयोदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग की परियोजना निदेशक प्रीति माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का नाम में परिवर्तन कर ''दीनदयाल अन्तयोदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है।

Press Coverage

HIGH-TECH SOON

Bundi may be first Indian city to get detailed digital mapping

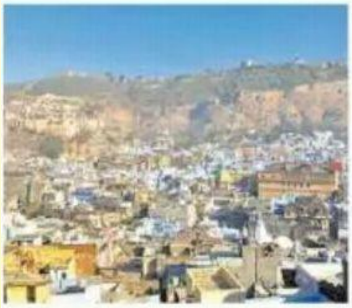

Rajiv Saxena

Bundi: Bundi, a popular tourist destination, is going to be the first city of the country to have digital mapping with comprehensive database of houses, buildings, constructions and monuments with detailed information. A Jaipur-based company has been hired to complete the digital mapping of the Bundi city.

Pankaj Kumar Mangal, Commissioner, Bundi Municipal Council informed that Bundi is the first city in India to have digital mapping of its demographical and geographical information.

According to Mangal, Hyderabad is the first city to have such kind of digital mapping, but, it is not so comprehensive like that of Bundi.

> *We have identified 1,069 bighas of land as government land. A drive to remove encroachments over the land will begin soon. The digital mapping will check illegal constructions.*
>
> PANKAJ K MANGAL, *commissioner, Bundi Municipal Council*

The digitalisation of the tourist city includes small streets, trees, electric and telephone lines, poles, pillars along with the details of houses, buildings, monuments and shops, Mangal added.

The digitalisation process is still going on and is likely to be completed within next six months, Mangal said.

He also added that the details accessed from digital mapping of the city so far have helped identify the government land and illegal encroachments. In 32 colonies, over 100 bighas of government land, encroachments were removed after they were identified through digital map of the city, Mangal said.

"We have identified 1,069 bighas of land as government land and now the drive will continue to remove encroachments over government land. The digital mapping will check the unplanned and illegal constructions," he added.

Once the process is over, people can easily access the database of the location and dimension of a house or any other construction, its owner and occupants. The initiative was taken in view of good governance as per the RTI Act enabling one to get any sort of information just a click away, said Mangal.

This initiative will also bring accountability and transparency in working of the government. Be it issuance of any document or license or permission, the officials concerned office will be able to check and verify the details with digital mapping.

After digitalisation, not only the government but also the common man will be able to keep an eye over his property and assets, the commissioner added.

Digital map gives Bundi worm's-eye view of town

INNOVATIVE INITIATIVE The comprehensive database will have demographical and geographical information

Aabshar H Quazi

KOTA: Bundi is on its way to become the first town in Rajasthan to have a comprehensive digital database of its demographical and geographical information.

The digitisation process is still under way to include details of all houses, shops, drains, roads, trees, and electricity and phone lines, but the benefits of this initiative by the Bundi Municipal Council are already visible.

For one, it has made identifying encroachments easier.

"The municipal council has already removed encroachments in 32 colonies of Bundi town on the basis of the digitised information," said municipal commissioner Pankaj Kumar Mangal.

Once complete, the database will provide the location and dimensions of a house or any other construction, and also the details of its owners and residents.

> The dimensions of the shops, trees, electricity poles, drains, roads, high-tension lines, telephone poles, land and all other physical entities can be sought through the digitised database of Bundi town
>
> PANKAJ KUMAR MANGAL, municipal commissioner

"The dimensions of the shops, trees, electricity poles, drains, roads, high-tension lines, telephone poles, land and all other physical entities can be sought through the digitised database of Bundi town, which is a unique initiative."

Around 7,000 out of 22,000 households in town have already been surveyed, and the remaining is expected to be covered in less than a year.

"While Google images give around 97% accuracy, they do not provide details. The digitised database of Bundi town will give 100% accuracy with details of even the dimensions and other properties of the entities."

Jaipur-based R-Tech Infra Associates has been hired for the digitisation work. The cumulative information collected will then be superimposed for preparation of a detailed digital image of Bundi town, explained Mangal.

"People will also be able to keep tab on their property, which will prevent unauthorised occupation since every entity will have unique identity code."

"The project will also act as a master database for all kind of spatial projects/detailed project reports," he added.

1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 5 और शहर अमृत मिशन सिटी में

राज्य सरकार लंबे समय से शहरी विकास मंत्रालय से कर रही थी मांग

श्रवण सिंह राठौड़ | नई दिल्ली

प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर देश की स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने के बाद अब राजस्थान के पांच नए शहरों को केंद्र सरकार जल्द ही अमृत मिशन सिटी में शामिल करने जा रही है। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले इन शहरों में बाड़मेर, नागौर का मकराना, करौली, बांसवाड़ा और सरदार शहर शामिल है। पांच छोटे शहरों का विकास भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा। किल्लत झेल रहे इन शहरों में साफ पानी, सीवरेज, सेप्टेज, बारिश के पानी का संरक्षण और निकासी, शहरी परिवहन और ग्रीनरी आदि का लाभ मिलेगा।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को अब लोकसभा की पिनाकी मिश्रा के नेतृत्व वाली 30 सांसद सदस्य वाली शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने इस बारे में स्पष्ट सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि शहरी विकास मंत्रालय ने राजस्थान के इन पांच शहरों को पहले अमृत मिशन में शामिल नहीं किया था। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार बार- बार शहरी विकास मंत्रालय से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले इन शहरों को अमृत मिशन में शामिल करने का आग्रह करती रही है। जबकि समिति ने माना कि मापदंडों के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद इन्हें अभी तक शामिल नहीं किया है। कुछ अन्य राज्यों की ओर से भी ऐसे ही अनुरोध किए गए है। अमृत मिशन के तहत देश के एक लाख जनसंख्या वाले 493 शहरों का चयन किया जा रहा है।

▪ राजस्थान के पांच शहरों को अमृत मिशन में शामिल किए जाने को लेकर आग्रह किया था। समिति ने मापदंडों पर गौर किया। - रामचरण बोहरा, सांसद जयपुर और सदस्य शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

OUR PARTNER'S

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
Leaders at the Core of Better Communities

US-AEP
United States-Asia Environmental Partnership

NIUA
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
National Institute of Urban Affairs

City Managers' Association Rajasthan, Room. No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966, www.cmar-india-org, E mail-cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on the website at: http://www.cmar-india.org/